

किसानों को 88638 करोड़ का फसल ऋण

एमपी के लिए वार्षिक ऋण योजना 5 लाख 856 करोड़ तय

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 3 जुलाई. मप्र के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स सलिटि ने वार्षिक साख योजना 2026-27 की अवाधि के लिए राज्य स्तरीय क्रेडिट प्लान जारी कर दिया है, अलग- अलग सेक्टरों को मिलाकर मप्र के लिए कुल 5 लाख 856 करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान तय किया गया है. इसमें किसानों के लिए भी 88638 करोड़ रुपए की फसल ऋण की राशि देने की योजना बनाई गई है. मुख्य सचिव अनुसंग जैन ने मंत्रालय में शक्रवार को वित्त विभाग के



अधिकारियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान मुख्य सचिव ने समन्वयक से कहा कि वे जिलों से प्राप्त जिला स्तरीय

क्रेडिट प्लान का हर हाल में क्रियान्वयन कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं. मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक साख योजना 2026-27 का विमोचन कर जारी की. जारी क्रेडिट प्लान के अनुसार कुल वार्षिक ऋण योजना रुपए 5,00,856 करोड़ निर्धारित की गई है. जो गत वर्ष के लक्ष्य 4,19,110 करोड़ रुपए का 119.50 प्रतिशत है. कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फार्म क्रेडिट के लिए 1,28,866 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया

एमएसएमई के लिए 162967 करोड़ रुपए का लक्ष्य

इसी क्रम में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1,62,967 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष के लक्ष्य का 121.64 प्रतिशत तथा उपलब्धि का 120.90 प्रतिशत है. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है. इस क्षेत्र का लक्ष्य गत वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 731.11 प्रतिशत तथा उपलब्धि की तुलना में 167.70 प्रतिशत बढ़ाया गया है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कुल 3,45,915 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कुल वार्षिक ऋण योजना का लगभग 69 प्रतिशत है तथा गत वर्ष के लक्ष्य का 117.76 प्रतिशत एवं उपलब्धि का 121.58 प्रतिशत है. बैंडक में विश्वास व्यक्त किया गया कि समस्त बैंकों के साथ ही राज्य शासन के विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयास से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य में समथबद्ध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी.

गया है जो गत वर्ष के लक्ष्य का 106.56 प्रतिशत तथा उपलब्धि का 120.56 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह फसल ऋण का लक्ष्य

नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के आरोप में तीन गिरफ्तार

भिण्ड. जिले के लहार क्षेत्र में 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार दबोह निवासी किशोरी अपनी बुआ के घर लहार आई हुई थी. बुधवार दोपहर वह लहार सिविल अस्पताल के पास खड़ी थी, तभी एक कार में सवार सुमित वाल्मीकि, नितिन दौहरे तथा एक नाबालिग उसे कथित तौर पर जबरन वाहन में बैठाकर दबोह की ओर ले गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपियों के वाहन का पीछा किया. पीछा होते देख आरोपी घबरा गए और दबोह बाइपास पर किशोरी को छोड़कर फरार हो गए.



एक नजर में

रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया मेडिकल ऑफिसर
शहडोल. भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई में शुक्रवार को शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उफरी के मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेश चंद्र शर्मा को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी चिकित्सक शिकायतकर्ता की पत्नी का सलमनीकरण (अटैचमेंट) आदेश निरस्त कराने एवं रवानगी नहीं देने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था.

मुख्य आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इनकार

राजा रघुवंशी हत्याकांड :

इंदौर, 3 जुलाई. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेघालय हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आदेश पर कुछ आपत्तियां जरूर हैं, लेकिन आरोपी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है.

ऐसे में इस स्तर पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जाएगी. हालांकि अदालत ने मेघालय सरकार की चुनौती याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की

सुनवाई स्वीकार कर ली है. सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यह सुनियोजित हत्या का मामला है. आरोप है कि मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर शाव खाई में फेंक दिया था और बाद में फरार हो गई थी. सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि गिरफ्तारी दस्तावेज में हत्या की धारा की जगह दूसरी धारा अंकित होना महज टाइपिंग की त्रुटि थी. मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट किए जा चुके थे, इसलिए केवल इस तकनीकी गलती के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था.

दिग्विजय ने किया पदयात्रा का ऐलान

उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे यात्रा

विशेष संवाददाता
भोपाल, 3 जुलाई. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के विरोध में उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करने की घोषणा की है. यह पदयात्रा 2 अक्टूबर 2026 से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होगी.

शुक्रवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने 'चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित' लिखे पोस्टर भी प्रदर्शित किए. उन्होंने



आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे और चढ़ावे के साथ कथित रूप से अनियमितताएं कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं ने दो बार

उदारतापूर्वक सहयोग दिया, लेकिन अब प्रतिदिन मिलने वाले चढ़ावे का 10 से 20 प्रतिशत तक कथित रूप से गबन किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह न्यायालय में याचिका दायर कर अपने द्वारा दिए गए चंदे की राशि वापस मांगेंगे. यदि राशि वापस मिलती है तो उसे रामालय ट्रस्ट को दान करेंगे.

पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित तीन गिरफ्तार

नरसिंहपुर. पुलिस ने बारूवा पुल के पास मिले एक व्यक्ति के शव के मामले का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी सहित तीन आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने बताया कि 30 जून को कोतवाली थाना क्षेत्र के बारूवा पुल के समीप झाड़ियों में एक शव मिला था, जिसकी पहचान बहोरीपार निवासी तुलसीराम मेहरा (40) के रूप में हुई थी. हत्या की आशंका के चलते मामले की गहन जांच की गई. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी सरोज मेहरा और उसके कथित प्रेमी महेंद्र मेहरा के बीच संबंध थे, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

राम मंदिर मामला : महिला कांग्रेस का सदबुद्धि यज्ञ

विशेष संवाददाता
भोपाल, 3 जुलाई . राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में सदबुद्धि यज्ञ, भजन-कीर्तन और एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेतृत्व को सदबुद्धि देने की कामना करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कथित चंदा घोटाले के दोषियों के



विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की. नेताओं का कहना था कि करोड़ों रामभक्तों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए सहयोग दिया था, इसलिए यदि धन के उपयोग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाया

जाना चाहिए. दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था. यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित होते हैं तो वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अयोध्या में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे.

प्राचीन काली मंदिर से 20 किलो चांदी चोरी, दूसरी वारदात से दहशत

सतना. जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव स्थित प्राचीन काली मंदिर में चोरों ने देवी के सिंहासन में लगी लगभग 20 किलोग्राम चांदी चोरी कर ली. इसी मंदिर में दो जून को हुई चांदी चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सूत्रों के अनुसार एक और दो जुलाई की दरमियानी रात अज्ञात बदमाश मंदिर में घुसे और देवी के सिंहासन में लगी लगभग 20 किलोग्राम चांदी उखाड़कर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही घटना की जांच की जा रही है.

कांग्रेस का अनुशासन पर सख्त रुख

राकेश यादव निष्कासित, दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

विशेष संवाददाता
भोपाल, 3 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन में अनुशासन और पार्टी की रीति-नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों तथा लगातार अनुशासनहीनता के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है. इसी क्रम में पार्टी ने राकेश यादव को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राकेश यादव को पूर्व में कई बार चेतावनी देने और समझाइश के बावजूद उन्होंने पार्टी



विरोधी गतिविधियां जारी रखीं. उनके आचरण से संगठन की छवि प्रभावित हुई, जिसके चलते प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उनके खिलाफ यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. वहीं, प्रदेश

कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. संजय कमल ने दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. इसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस की महासचिव निधि चतुर्वेदी को भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित अनुशासनहीन टिप्पणियां करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है. उन्हें भी सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

प्रियंका किरार, जो महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी की नीति और अनुशासन के विपरीत टिप्पणी करने का आरोप है. उन्हें सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पेज एक का शेष

रिपोर्ट से पहले ही यूसीसी विधेयक तैयार

इस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक के बाद यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब इसे मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी की गई है, लेकिन यह कमेटी की चेयरपर्सन की ओर से मिले समय पर तय होगा. बताया जा रहा है कि यदि चेयरपर्सन किसी कारणवश राजधानी भोपाल आने में असमर्थ रही

तो कमेटी की ओर से रिटायर्ड आईएसएस शत्रुघ्न सिंह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यूसीसी को लेकर तैयार सफरिशें सौंप देंगे. धर्म बदलने वाले आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहेंगे: देश के कई राज्यों के साथ ही मप्र में तेजी से धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो

रही हैं. विशेष रूप से सनातन धर्म के मानने वालों को टारगेट किया जा रहा है. इसमें भी आदिवासी समुदाय को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है. पैसों सहित अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय को विशेष रूप से इसाई धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं.

अमित शाह या नीतीश हो सकते हैं उप प्रधानमंत्री

इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों से जयपुर के दूसरे क्रम के कई नेता नीतीश कुमार के अनुभवों को आधार बनाकर उन्हें उपप्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी कर रहे हैं. इस संदर्भ में राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय बड़े प्रदेश से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री या उपप्रधानमंत्री नहीं बना है ऐसे में संभव है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय संदेश को स्थापित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय व राजनीतिक संतुलन को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी कोई अप्रत्याशित फैसला कर लें. जानकार बता रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास गवाह है कि उप-प्रधानमंत्री का पद हमेशा गठबंधन को बचाए रखने या पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन साधने के लिए दिया गया है.

विकास श्रीरामानुज संस्कृत परिसर वैदिक अध्ययन, ज्ञान परम्परा के अध्ययन-अध्यापन का बनेगा महत्वपूर्ण केंद्र

243 पदों के सृजन का प्रस्ताव शीघ्र करें तैयार

भोपाल, 3 जुलाई . उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्रीरामानुज संस्कृत परिसर, लक्ष्मण बाग (रीवा) के सशक्तीकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की.



सृजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इनमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं, जिन्हें तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भर्ने की योजना है.

उन्होंने बताया कि पदों की स्वीकृति से परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा. इससे संस्कृत भाषा, वैदिक ज्ञान, भारतीय दर्शन और पारंपरिक विद्या प्रणालियों के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार को नई गति मिलेगी. बैठक में बताया गया कि श्रीरामानुज संस्कृत परिसर की स्थापना मध्यप्रदेश शासन ने 5 अक्टूबर 2023 को की थी. वर्तमान में यहां सीमित संसाधनों के साथ शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य संचालित हो रहे हैं. परिसर में वेद, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, योग, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत, मानविकी, पौराणिक, हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षाशास्त्र सहित विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है.

उन्होंने निर्देश दिए कि परिसर के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं. उन्होंने कहा कि पर्याप्त

मानव संसाधन उपलब्ध होने से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध मार्गदर्शन और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी.



ऊर्जा प्रबंधकों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) की

राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऑनलाइन पंजीकरण करें

www.nceexam.in

विवरण पत्र उपपर दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ		परीक्षा कार्यक्रम	
पंजीकरण शुरू	29 जून 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे से	क़्रम संख्या	तारीख
पंजीकरण बंद	30 जुलाई 2026 सायं 17:00 बजे तक	1	25 सितंबर 2026
		2	26 सितंबर 2026
		3	27 सितंबर 2026

पेपर/पुस्तक संख्या

पहला, दूसरा

तीसरा, चौथा

पांचवां, छठा (भवन)

www.beedindia.gov.in

beedindiaigital

bureauofenergyefficiency